INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 12 | JANUARY – 2026

"रीवा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एवं बाजार संतुलन का वाणिज्यिक मूल्यांकन"

पूजा शुक्ला[1], डॉ. सतीश कुमार गर्ग[2]
[1]शोधार्थी वाणिज्य, शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर (म.प्र.)
[2]प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य, शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर (म.प्र.)

सारांश –

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य रीवा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता तथा स्थानीय बाजार संतुलन पर पड़ने वाले वाणिज्यिक प्रभावों का विश्लेषण करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार की एक प्रमुख खाद्य सुरक्षा योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दरों पर आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। वाणिज्यिक दृष्टिकोण से यह प्रणाली केवल सामाजिक कल्याण का साधन न होकर बाजार में सरकारी हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है, जो मांग–आपूर्ति संतुलन, मूल्य स्थिरता तथा उपभोक्ता क्रय–शक्ति को प्रभावित करती है। रीवा जिला मध्यप्रदेश का एक कृषि प्रधान एवं ग्रामीण बहुल जिला है, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा भाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर है। इस शोध में प्राथमिक समंकों एवं द्वितीयक समंकों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने एक ओर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है, वहीं दूसरी ओर खुले बाजार में खाद्यान्न की अत्यधिक मांग को नियंत्रित कर मूल्य अस्थिरता को कम किया है। अध्ययन से यह भी ज्ञात किया गया है कि वितरण व्यवस्था में कुछ प्रशासनिक एवं संरचनात्मक कमियाँ विद्यमान हैं, तथापि समग्र रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली रीवा जिले में खाद्य बाजार को स्थिरता प्रदान करने में सफल रही है। इस प्रकार यह शोध सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ बाजार संतुलन का एक प्रभावी वाणिज्यिक माध्यम सिद्ध करता है।

मुख्य शब्द : सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, बाजार संतुलन, वाणिज्यिक मूल्यांकन, रीवा जिला, मूल्य स्थिरता।

प्रस्तावना –

खाद्य सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिरता, सामाजिक न्याय एवं सतत् विकास का एक अनिवार्य घटक मानी जाती है। विशेषकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, जहाँ आय असमानता एवं गरीबी व्यापक रूप से विद्यमान होती है, वहाँ खाद्य सुरक्षा केवल कृषि उत्पादन तक सीमित न रहकर वितरण व्यवस्था, मूल्य नियंत्रण तथा उपभोक्ता की क्रय–शक्ति से भी गहराई से जुड़ी होती है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की प्रमुख आर्थिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी है।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने खाद्यान्न संकट, मूल्य अस्थिरता तथा गरीबी से निपटने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली को एक संस्थागत स्वरूप प्रदान किया है। प्रारंभ में यह प्रणाली शहरी क्षेत्रों तक

सीमित रही, किंतु समय के साथ इसे ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है। वाणिज्यिक अध्ययन के दृष्टिकोण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बाजार में सरकारी हस्तक्षेप (Government Market Intervention) के रूप में देखा जाता है, जिसका उद्देश्य बाजार विफलताओं को दूर करना है।

रीवा जिला मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र का एक प्रमुख जिला है, जहाँ कृषि एवं कृषि–आधारित गतिविधियाँ अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। जिले की सामाजिक–आर्थिक संरचना में निम्न एवं मध्यम आय वर्ग की प्रधानता है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। इस प्रणाली के माध्यम से गेहूँ, चावल एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उपभोक्ताओं को बाजार मूल्य से कम दर पर उपलब्ध कराई जाती है।

वाणिज्यिक सिद्धांतों के अनुसार बाजार संतुलन मांग और आपूर्ति की पारस्परिक क्रिया से निर्धारित होता है। जब सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न की अतिरिक्त आपूर्ति उपलब्ध कराती है, तब खुले बाजार में मांग का दबाव कम हो जाता है। परिणामस्वरूप मूल्य स्थिरता बनी रहती है और जमाखोरी तथा कालाबाजारी जैसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण संभव हो पाता है।

रीवा जिले के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अध्ययन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह न केवल खाद्य सुरक्षा का माध्यम है, बल्कि स्थानीय बाजार संरचना, खुदरा व्यापार एवं उपभोक्ता व्यवहार को भी प्रभावित करती है। प्रस्तुत शोध–पत्र में इसी वाणिज्यिक परिप्रेक्ष्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका का विश्लेषण अध्ययन किया गया है।

शोध उद्देश्य –

शोध के उद्देश्य किसी भी अध्ययन की दिशा एवं सीमाओं को स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत शोध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एवं बाजार संतुलन के वाणिज्यिक आयामों को समझने का प्रयास किया गया है। रीवा जिले को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित करने का कारण यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर उपभोक्ताओं की उच्च निर्भरता एवं कृषि–प्रधान बाजार संरचना है। वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अंतर्गत यह अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह मूल्य निर्धारण, मांग–आपूर्ति तथा उपभोक्ता व्यवहार जैसे मूलभूत सिद्धांतों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

(1) रीवा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा की स्थिति का वाणिज्यिक मूल्यांकन करना।
(2) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थानीय बाजार संतुलन एवं मूल्य स्थिरता पर प्रभाव का विश्लेषण करना।
(3) उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

शोध विधि –

प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध विधि को अपनाया गया है। अध्ययन को वस्तुनिष्ठ एवं विश्वसनीय बनाने हेतु प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के समंकों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक समंक रीवा जिले के चयनित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से 300 उत्तरदाताओं से प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधि द्वारा संकलित किए गए हैं। उत्तरदाताओं का चयन यादृच्छिक नमूना विधि से किया गया है। द्वितीयक समंकों के अंतर्गत भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन की रिपोर्टें, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रकाशन, जिला सांख्यिकीय पुस्तिकाएँ, शोध–पत्र तथा संबंधित पुस्तकें सम्मिलित की गई हैं। समंकों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत विधि एवं तुलनात्मक विश्लेषण का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण अध्ययन में मांग–आपूर्ति सिद्धांत एवं मूल्य सिद्धांत को वाणिज्यिक आधार के रूप में अपनाया गया है।

विश्लेषण –

प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक प्रमुख साधन है। अधिकांश उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उन्हें न्यूनतम मूल्य पर नियमित रूप से खाद्यान्न प्राप्त होता है, जिससे उनकी

खुले बाजार पर निर्भरता कम हुई है। वाणिज्यिक दृष्टिकोण से यह स्थिति बाजार संतुलन को स्थिरता प्रदान करती है। जब उपभोक्ताओं की एक बड़ी संख्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तब खुले बाजार में मांग का दबाव कम हो जाता है। इससे खाद्यान्न के मूल्य में अत्यधिक उतार–चढ़ाव की संभावना घट जाती है। हालाँकि कुछ उत्तरदाताओं ने वितरण में अनियमितता एवं गुणवत्ता संबंधी समस्याओं की ओर भी संकेत किया, किंतु समग्र रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने रीवा जिले में खाद्य सुरक्षा एवं बाजार स्थिरता को सुदृढ़ किया है। यह प्रणाली एक प्रभावी वाणिज्यिक हस्तक्षेप के रूप में कार्य कर रही है। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रति उपभोक्ता प्रतिक्रिया के संबंध में सारणी क्रमांक 01 में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है, जो इस प्रकार है –

सारणी क्रमांक–01

अध्ययन क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रति उपभोक्ता प्रतिक्रिया संबंधी विवरण

क्रमांक	विवरण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1.	खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है	90	30.00
2.	बाजार मूल्य नियंत्रण में सहायक	75	25.00
3.	क्रय–शक्ति में वृद्धि	80	26.67
4.	वितरण व्यवस्था में समस्याएँ	55	18.33
योग		300	100.00

स्रोत : प्राथमिक सर्वेक्षण, 2024–25

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि कुल 300 उत्तरदाताओं में से 30 प्रतिशत ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रमुख साधन माना है। 25 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि यह प्रणाली बाजार मूल्य को नियंत्रित करने में सहायक है, जो वाणिज्यिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। 26.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कारण उनकी क्रय–शक्ति में वृद्धि हुई है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता आई है। वहीं 18.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने वितरण व्यवस्था में समस्याओं की ओर संकेत किया है, जो प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। समग्र रूप से यह प्रमाणित होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली रीवा जिले में खाद्य सुरक्षा एवं बाजार संतुलन दोनों में सकारात्मक भूमिका निभा रही है।

निष्कर्ष –

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष परिलक्षित होता है कि रीवा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ–साथ स्थानीय बाजार संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वाणिज्यिक दृष्टिकोण से यह प्रणाली मांग–आपूर्ति के असंतुलन को नियंत्रित करने का एक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दरों पर खाद्यान्न की उपलब्धता ने उपभोक्ताओं की क्रय–शक्ति को सुरक्षित रखा है तथा खुले बाजार में मूल्य अस्थिरता को सीमित किया है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है, बल्कि बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन भी बना रहा है। यद्यपि वितरण व्यवस्था में कुछ संरचनात्मक एवं प्रशासनिक कमियाँ विद्यमान हैं, तथापि यदि इन्हें दूर किया जाए तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली रीवा जिले में खाद्य सुरक्षा एवं बाजार संतुलन का एक सशक्त वाणिज्यिक उपकरण है।

संदर्भ –

1. शर्मा, आर. के., भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नई दिल्ली, 2018
2. मिश्रा, एस. पी., खाद्य सुरक्षा एवं बाजार अर्थशास्त्र, दिल्ली, 2019
3. मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति प्रतिवेदन, भोपाल, 2020

4. सिंह, ए. के., कृषि विपणन एवं मूल्य स्थिरता, लखनऊ, 2021
5. योजना आयोग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन, नई दिल्ली, 2022
6. वर्मा, एन., वाणिज्य एवं कल्याण अर्थशास्त्र, जयपुर, 2023
7. जिला सांख्यिकी कार्यालय, रीवा, जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, रीवा, 2024